2.	Tamil Nadu	Nagapattanam Tiruvarur Pannirsclvam
3.	Orissa	Bolangir Kalahandi Naupada Kcndrapara Jajpur
4.	Madhya Pradesh	Bastar Sarguja
5.	Bihar	Sitamari Darbangha Madhubani Samastipur Khagaria Palamau Vaishali
6.	Maharashtra	Amravati
7.	Assam	Nagaon N. Lakimpur Dhcmaji Nalbari
S.	Karnataka	Bijapur
9.	Rajasthan	Jhunjunu

Total No. of Districts 25

रेल के माध्यम से पश्चिमोत्तर क्षेत्रों से जुड़े शहर

*487. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों के साथ अब तक कितने शहरों को रेल से जोड़ा गया है;

(ख) कितने शहरों को उक्त क्षेत्रों के साथ जोड़े जाने की संभावना है;

(ग) क्या गोधरा, अहमदाबाद, राजकोट, गांधीधाम और वडोदरा शहरों को सीधी रेल लाइन द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्रों से जोड़े जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (**श्री राम विलास पासवान**) : (क) भारत में सभी महत्वपूर्ण शहर रेल द्वारा देश के उत्तर पश्चिमी भाग में महत्वपूर्ण शहरों तथा कस्बों से जुड़े हुए हैं।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ग) ये शहर पहले सी ही सीधे मार्ग द्वारा बरास्ता आगरा, लखनऊ, बरौनी तथा बरास्ता भोपाल, इलाहाबाद, पटना देश के उत्तर पूर्वी भाग से जुड़े हुए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जिन नई लाइनों पर काम चल रहा है, उनके पूरा हो जाने पर देश के पश्चिमोत्तर भाग के निम्नलिखित शहरों के रेल से जुड़ जाने की आशा है:-

राज्य	**शहर**
आंध्र प्रदेश	करीमनगर
असम और पूर्वोत्तर राज्य	1. अगरतला
	2. गोलपाड़ा
	3. करोंग
	4. ईटानगर
बिहार	दुमका
जम्मू और कश्मीर	1. बारामूला
	2. श्रीनगर
	3. अनंतनाग
	4. ऊधमपुर
कर्नाटक	1. हरपनहल्ली
	2. चिकमगलूर
मध्य प्रदेश	1. टीकमगढ़
	2. छतरपुर
	3. पत्रा
	4. सीधी
	5. झाबुआ
	6. धार
महारष्ट्र	बीड़
उड़ीसा	केंडुझारगढ़
पश्चिम बंगाल	बालूरघाट

नोट:

इस विवरण के प्रयोजन के लिए निम्न लिखित स्थानों को शहरों के रूप में परिभाषित किया गया है :-

1. नगर प्रतिकर भत्ते के प्रयोजनों के लिए भारत सरकार द्वारा 'ए', 'बी' और 'बी2' श्रेणी के शहरों के रूप में वर्गीकृत स्थान।

2. सभी जिला मुख्यालय।

Cases pending before State Consumer Redressal Commissions

*488. SHRI MD. SALIM: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the total number of cases pending before the State Consumer Redressal Commissions, State-wise; and

(b) the steps Government propose" for the quick disposal of the cases?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) A statement showing the number of cases pending before the State Consumer Disputes Redressal Commission, State-wise, as reported by the StatesAJT, is enclosed *See* below)

(b) Poor infrastructure lack of monitoring, frequent adjournments, non-filling up of the posts of the Presidents/ members in consumer courts are some of the reasons for delayed disposal of the cases. Some of the steps taken by the Government for removing some of these problems are as follows:—

(i) Under the scheme for the first, time, one-time grant for strengthening the infrastructure of the State and district level consumer courts, the Central Government has provided Rs. 54.62 crores to the States/UTs during 1995-97.

(ii) Central/State Governments and the National Consumer Dispute Redressal Commission arc monitoring the working of these consumer courts through periodical reports.

(iii) Central Government has given special emphasis on monitoring and filling up the vacancies of Presidents/Members in the consumer courts in order to expediting the clearance of pending cases.

(iv) The Ministry has written to the State Governments to hold periodical meetings with the Presidents